



The
ACHIEVERS
IAS ACADEMY
PATNA

Daily
NEWS CHRONICLE

IDEAL FOR

For UPSC/BPSC & For other Exams

Hindi

NEWS CREDIT

PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express...

NEWS COVERED

Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics...



Thursday, August 27, 2026



+91 8434931877



www.achieversiaspatna.co.in



achieversiaspatna@gmail.com

दिन की प्रमुख घटनाएं

- **भारत और चीन** सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान के प्रयास जारी रखने पर सहमत।
- **सीएसआईआर-एनएएल** ने भारत की रक्षा और एयरोस्पेस क्षमताओं को मजबूत करने वाले तीन स्वदेशी गैस टरबाइन इंजनों का अनावरण किया।
- प्रकाशन विभाग ने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए **सात एफआईपी पुरस्कार** जीते।
- **तमिलनाडु** ने तीन एलपीजी सिलेंडरों के लिए वार्षिक प्रतिपूर्ति की घोषणा की, जिससे 1.30 करोड़ पात्र परिवार लाभान्वित होंगे।
- **ई-श्रम पोर्टल** ने 31.89 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के साथ पांच साल पूरे किए।
- पीएनजीआरबी ने छह राज्यों में 1,800 किलोमीटर लंबी नई एलपीजी पाइपलाइनों को मंजूरी दी, जिससे ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा।
- भारतीय डाक ने **डाक सेवा ऐप लॉन्च किया**, जो सुविधाजनक डोरस्टेप डाक और लॉजिस्टिक्स सेवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाता है।
- **सीबीआईसी और फार्मेक्सिल** ने फार्मास्युटिकल निर्यात को मजबूत करने और उत्पादों के डायवर्सन को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- **सिटीग्रुप और एक्सिस बैंक** ने विदेशी मुद्रा जमा के माध्यम से एनआरआई डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की।
- भारत ने पहली पूरी तरह से स्वदेशी **एके-203 शोर असॉल्ट राइफल** का परीक्षण किया, रक्षा आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाया।

भारत-चीन सीमा प्रश्न के राजनीतिक समाधान के लिए प्रयास जारी रखने पर सहमत



- भारत और चीन अपने समग्र और दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए सीमा प्रश्न के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम करना जारी रखने पर सहमत हुए हैं। बीजिंग में आयोजित भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) वार्ता के 25वें दौर के दौरान यह सहमति सामने आई।

मुख्य विचार:

- वार्ता की सह-अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी, चीन के विशेष प्रतिनिधि ने की।
- भारत ने जोर देकर कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2024 में कज़ान और अगस्त 2025 में तियानजिन में हुई समझौतों को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की।
- दोनों देशों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और तीन निर्दिष्ट सीमा व्यापार मार्गों के माध्यम से सीमा व्यापार सहित लोगों से लोगों के बीच संपर्क के विस्तार का भी स्वागत किया।
- विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का अगला दौर 2027 में भारत में होने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि:

- भारत और चीन लगभग 3,800 किलोमीटर की विवादित सीमा साझा करते हैं। राजनयिक और सैन्य स्तर की कई दौर की वार्ता के बावजूद सीमा मुद्दा अनसुलझा रहा है।
- 2020 की गलवान घाटी में झड़प के कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर लंबे समय तक सैन्य गतिरोध रहा। बाद की बातचीत के परिणामस्वरूप विघटन हुआ और स्थिरता बहाल करने के प्रयास हुए।

महत्व

- सीमा स्थिरता: एलएसी पर शांति बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है।
- राजनयिक जुड़ाव: निरंतर एसआर वार्ता सीमा विवाद को संबोधित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय तंत्र प्रदान करती है।
- क्षेत्रीय स्थिरता: स्थिर भारत-चीन संबंधों का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
- आर्थिक संबंध: बेहतर सीमा की स्थिति व्यापक आर्थिक और लोगों से लोगों के जुड़ाव का समर्थन कर सकती है।

अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

व्यक्तियों	विवरण
25वीं एसआर वार्ता	अगस्त 2026
कार्यक्रम-स्थल	बीजिंग, चीन
भारत के विशेष प्रतिनिधि	अजीत डोभाल
चीन के विशेष प्रतिनिधि	वांग यी
अगली एसआर वार्ता	भारत, 2027
मुख्य मुद्दा	भारत-चीन सीमा विवाद
सीमा रेखा	वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी)
हाल के मील के पत्थर	कज़ान 2024 और तियानजिन 2025 समझ
मेजर 2020 झड़प	गलवान घाटी में झड़प

सीएसआईआर ने तीन स्वदेशी सूक्ष्म और लघु गैस टरबाइन इंजनों का अनावरण किया



- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं (सीएसआईआर-एनएएल) ने भारत की स्वदेशी रक्षा और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई दिल्ली में तीन स्वदेशी रूप से विकसित सूक्ष्म और लघु गैस टरबाइन इंजनों का अनावरण किया है।
- इंजनों का उद्देश्य विशेष रूप से भारत की मानव रहित रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है।

तीन इंजन हैं:

इंजन	धक्का
एनजे-05	5 किलो जोर
एनजे-50	50 किलो जोर
एनजे-100	100 किलो जोर

- इन कॉम्पैक्ट प्रणोदन प्रणालियों की परिकल्पना सामरिक मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी), ड्रोन इंटरसेप्टर और कॉम्पैक्ट मिसाइल प्रणालियों सहित अनुप्रयोगों के लिए की गई है।
- यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रणोदन प्रणाली आधुनिक एयरोस्पेस और रक्षा प्लेटफार्मों का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऐसे इंजनों की स्वदेशी उपलब्धता आयातित प्रणोदन प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को कम करने और भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने में मदद कर सकती है।
- सीएसआईआर की महानिदेशक और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की सचिव डॉ. एन. कलैसेल्वी ने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में विशेष प्रणोदन उप-प्रणालियों के स्वदेशी विकास को बताया।

सीएसआईआर-एनएएल की भूमिका:

- सीएसआईआर-नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (सीएसआईआर-एनएएल) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत एक प्रमुख भारतीय एयरोस्पेस अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। इसके काम में एयरोस्पेस संरचनाएं, विमान डिजाइन, उड़ान प्रणाली, प्रणोदन से संबंधित प्रौद्योगिकियां और मानव रहित सिस्टम शामिल हैं।

- सीएसआईआर-एनएएल ने रक्षा आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर इन इंजनों के निर्माण के लिए भारत के बढ़ते एयरोस्पेस स्टार्ट-अप और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता पर भी प्रकाश डाला।

महत्व

- रक्षा स्वदेशीकरण: विदेशी प्रणोदन प्रणालियों पर निर्भरता को कम करता है।
- ड्रोन इकोसिस्टम: भारत की बढ़ती यूएवी और काउंटर-ड्रोन क्षमताओं का समर्थन करता है।
- आत्मनिर्भर भारत: स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देता है।
- प्रौद्योगिकी विकास: भारत की एयरोस्पेस प्रणोदन क्षमताओं को मजबूत करता है।
- उद्योग की भागीदारी: भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस कंपनियों के लिए अवसर पैदा करता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

व्यक्तियों	विवरण
संगठन	सीएसआईआर-एनएएल
मूल शरीर	सीएसआईआर
लाँच	25 अगस्त 2026
कार्यक्रम-स्थल	नई दिल्ली
इंजन	एनजे -05, एनजे -50, एनजे -100
धक्का	क्रमशः 5 किग्रा, 50 किग्रा और 100 किग्रा
अनुप्रयोगों	यूएवी, ड्रोन इंटरसेप्टर, कॉम्पैक्ट मिसाइलें
मुख्य उद्देश्य	स्वदेशी एयरोस्पेस प्रणोदन
पॉलिसी लिंकेज	आत्मनिर्भर भारत

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने पुस्तक निर्माण में उत्कृष्टता के लिए सात पुरस्कार जीते



- सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के प्रकाशन विभाग ने पुस्तक निर्माण 2026 में उत्कृष्टता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स (एफआईपी) अवार्ड्स में सात पुरस्कार जीते हैं। यह पुरस्कार हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू पुस्तकों, पत्रिकाओं और संदर्भ प्रकाशनों में प्रकाशन में उत्कृष्टता को मान्यता देता है।

मुख्य विचार:

- प्रकाशन विभाग ने विभिन्न श्रेणियों में चार द्वितीय पुरस्कार और तीन तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए।

दूसरा पुरस्कार विजेता प्रकाशन:

प्रकाशन	कोटि
भारत 2026 (हिंदी)	संदर्भ पुस्तकें-हिंदी श्रेणी
हमारी आशाओं के लिए पंख - खंड 2	सामान्य और व्यापार पुस्तकें-अंग्रेजी
योजना - जुलाई 2026, थीम "विकसित Bharat@2047"	पत्रिकाएं और घरेलू पत्रिकाएं-हिंदी
कुरुक्षेत्र - 1952 से एक ग्रामीण विकास मासिक	पत्रिकाएं और घर पत्रिकाएं-अंग्रेजी

तीसरा पुरस्कार विजेता प्रकाशन:

प्रकाशन	कोटि
धरती की सेहत	बच्चों की किताबें (हिंदी)
रंगोली रूप सुर लय की	कला और कॉफी टेबल बुक्स (हिंदी)
अजकल उर्दू – जुलाई 2026	पत्रिकाएं और गृह पत्रिकाएं (उर्दू)

- यह मान्यता राष्ट्रीय विकास, साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान और समकालीन मुद्दों पर सूचना के प्रसार में प्रभाग के योगदान पर प्रकाश डालती है।

प्रकाशन विभाग के बारे में:

- प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण प्रकाशन शाखा है। इसके प्रकाशन पाठकों को सरकारी नीतियों, विकास, संस्कृति, साहित्य और करंट अफेयर्स पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं।
- सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दो महत्वपूर्ण प्रकाशन योजना, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक मासिक पत्रिका और कुरुक्षेत्र हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण विकास और संबंधित मुद्दों पर केंद्रित हैं।

परीक्षा फोकस बिंदु:

व्यक्तियों	विवरण
संगठन	प्रकाशन विभाग
मंत्रालय	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सम्मान	7
धनराशि देना	पुस्तक निर्माण में उत्कृष्टता के लिए एफआईपी पुरस्कार 2026
पुरस्कार	4 सेकंड + 3 तीसरा
पहचानी गई भाषाएँ	हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू
प्रमुख प्रकाशन	योजना, कुरुक्षेत्र, भारत 2026
योजना थीम	विकास Bharat@2047
कुरुक्षेत्र	ग्रामीण विकास मासिक
महानिदेशक, प्रकाशन विभाग	डॉ. धीरज काकाडिया

तमिलनाडु सालाना 3 एलपीजी सिलेंडरों की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा



- तमिलनाडु सरकार ने अन्नपूर्णा सुपर सिक्स योजना के तहत पात्र परिवारों के लिए हर साल तीन घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की लागत की प्रतिपूर्ति की घोषणा की है। यह योजना पोंगल 2027 से शुरू की जाएगी।

मुख्य विचार:

- लाभार्थी: लगभग 1.30 करोड़ परिवार।
- वार्षिक व्यय: लगभग ₹4,000 करोड़ का अनुमान।
- पात्रता: ₹2.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार, मध्यम और सीमांत किसानों और विकलांग व्यक्तियों के परिवारों के साथ।
- भुगतान तंत्र: लाभार्थी पहले एलपीजी सिलेंडर खरीदेंगे। तेल विपणन कंपनियों से सिलेंडर से संबंधित डेटा प्राप्त करने के बाद, सरकार प्रतिपूर्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करेगी।

- यह योजना 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए तमिलनाडु वेनी कड़गम (TVK) सरकार के चुनावी वादों से जुड़ी है।

अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- योजना: अन्नपूर्णा सुपर सिक्स योजना
- राज्य: तमिलनाडु
- लॉन्च: पोंगल 2027
- लाभ: सालाना 3 एलपीजी सिलेंडरों की प्रतिपूर्ति
- लाभार्थी: लगभग 1.30 करोड़ परिवार
- अनुमानित लागत: ₹4,000 करोड़ सालाना
- पात्रता: ₹2.5 लाख तक की आय + निर्दिष्ट श्रेणियां
- भुगतान: प्रत्यक्ष बैंक-खाता हस्तांतरण
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने घोषणा की
- संबंधित नीति: एलपीजी सामर्थ्य और ऊर्जा पहुंच
- केंद्र सरकार लिंक – पीएमयूवाई
- यह पहल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लिए प्रासंगिक है, जिसे 2016 में गरीब घरों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। जबकि पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करता है, तमिलनाडु पहल एलपीजी रिफिल की आवर्ती लागत का समर्थन करने पर केंद्रित है।

ई-श्रम पोर्टल ने 5 साल पूरे किए



- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किए गए ई-श्रम पोर्टल ने 26 अगस्त 2026 को पांच साल पूरे कर लिए। यह भारत के असंगठित कार्यबल के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है।

मुख्य बिंदु

- ई-श्रम ने भारत का पहला आधार-सीडेड नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स (NDUW) बनाया।
- पंजीकृत श्रमिकों को एक अद्वितीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएन) प्राप्त होता है।
- पोर्टल ने 31.89 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए हैं।
- पंजीकृत श्रमिकों में महिलाएं 54.28% हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 45.72% है।
- सबसे बड़े व्यावसायिक समूहों में कृषि, घरेलू और घरेलू काम, निर्माण और परिधान शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे अधिक पंजीकरण वाले राज्यों में शामिल हैं।

ई-श्रम वन-स्टॉप समाधान:

- सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों को एक ही मंच के माध्यम से कई सामाजिक-सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए 21 अक्टूबर

2024 को ई-श्रम "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया। यह वर्तमान में 15 योजनाओं को एक साथ लाता है, जिनमें पीएम-एसवाईएम, पीएमएसबीवाई, पीएमजेबीवाई, ओएनओआरसी, पीएमवाई-जी और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शामिल हैं।

- पोर्टल को राष्ट्रीय करियर सेवा, स्किल इंडिया डिजिटल, माईस्कीम और मानधन जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे रोजगार और कौशल के अवसरों तक पहुंच का विस्तार हो रहा है।

महत्व

- सामाजिक सुरक्षा: असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और उनकी पहचान करने में मदद करता है।
- डिजिटल समावेशन: श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल पहचान बनाता है।
- पोर्टेबिलिटी: सभी स्थानों पर लाभों तक पहुंच का समर्थन करता है, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण।
- साक्ष्य-आधारित नीति: डेटाबेस सरकारों को लक्षित श्रम और कल्याण नीतियां तैयार करने में मदद करता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

व्यक्तियों	विवरण
ई-श्रम	असंगठित श्रमिकों के लिए डिजिटल डेटाबेस
लॉन्च किया गया	26 अगस्त 2021
मंत्रालय	श्रम और रोजगार
डेटाबेस	एनडीयूडब्ल्यू
अद्वितीय संख्या	यूएन
वर्तमान पंजीकरण	31.89+ करोड़
वन-स्टॉप समाधान	21 अक्टूबर 2024
मुख्य उद्देश्य	सामाजिक-सुरक्षा कवरेज और कल्याण वितरण

पीएनजीआरबी ने 1,800 किलोमीटर नई एलपीजी पाइपलाइनों को मंजूरी दी



- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने लगभग 1,800 किलोमीटर के नए एलपीजी पाइपलाइन बुनियादी ढांचे को अधिकृत किया है, जिसमें ₹7,000 करोड़ का अनुमानित निवेश शामिल है। ये परियोजनाएं छह राज्यों- तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और गोवा में होंगी।

मुख्य बिंदु

- तीन एलपीजी पाइपलाइन परियोजनाएं गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा विकसित की जाएंगी।

वे सम्मिलित करते हैं:

दूरी	पाइपलाइन मार्ग
556 किमी	चेरलापल्ली (तेलंगाना)-नागपुर (महाराष्ट्र)
611 किमी	झांसी (उत्तर प्रदेश)-सितामगंज (उत्तराखंड)
633 किमी	शिक्रापुर (महाराष्ट्र)-गोवा-हुबली (कर्नाटक)

- एक बार पूरा हो जाने के बाद, पीएनजीआरबी-अधिकृत कॉमन-कैरियर एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क लगभग 7,700 किमी से बढ़कर 9,500 किमी हो जाएगा, जो लगभग 23.5% का विस्तार है।

महत्व

- ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपने एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसमें आपूर्ति मुख्य रूप से तटीय टर्मिनलों के माध्यम से पहुंचती है। पाइपलाइनों से तटीय और आपूर्ति बिंदुओं से अंतर्देशीय खपत केंद्रों तक एलपीजी की आवाजाही में सुधार होगा।
- सड़क पर निर्भरता में कमी: परियोजनाओं का उद्देश्य सड़क मार्ग से एलपीजी टैंकर की आवाजाही को कम करना, सुरक्षा, रसद दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार करना है, जबकि संभावित रूप से भीड़भाड़ और उत्सर्जन को कम करना है।
- आपूर्ति लचीलापन: पाइपलाइन बुनियादी ढांचा आपूर्ति व्यवधानों और उच्च मांग की अवधि के दौरान अधिक लचीलापन प्रदान कर सकता है।

भारतीय डाक ने डोरस्टेप डाक सेवाओं के लिए 'डाक सेवा' ऐप लॉन्च किया



- संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने नागरिकों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डोरस्टेप डाक और लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए 'डाक सेवा' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय डाक की सेवाओं को अधिक सुलभ, सुविधाजनक और नागरिक-केंद्रित बनाना है।

मुख्य बिंदु

- डाक सेवा ऐप उपयोगकर्ताओं को डाकघर में जाने के बिना डाक सेवाओं को डिजिटल रूप से एक्सेस करने और डोरस्टेप पिकअप और डिलीवरी से संबंधित सेवाओं का अनुरोध करने में सक्षम बनाता है।

PNGRB के बारे में – परीक्षा तथ्य

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक है। यह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के नियंत्रित और विकसित करता है।
- बोर्ड की स्थापना पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- नियामक: PNGRB
- फुल फॉर्म: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
- नई पाइपलाइन की लंबाई: ~ 1,800 किमी
- निवेश: ₹7,000 करोड़
- राज्य: 6
- डैवलपर: गेल (इंडिया) लिमिटेड
- विस्तार के बाद नेटवर्क: ~ 9,500 किमी
- मौजूदा नेटवर्क: ~ 7,700 किमी
- भारत में सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन: कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन (2,757 किमी)।

- ऐप से भारतीय डाक के डिजिटल परिवर्तन को मजबूत करने की उम्मीद है, विशेष रूप से सुविधाजनक डाक और पार्सल सेवाओं की तलाश करने वाले ग्राहकों के लिए।

प्रमुख विशेषताएं

- डोरस्टेप डाक सेवाएं: ग्राहक अपने घरों से योग्य डाक सेवाओं का अनुरोध कर सकते हैं।
- डिजिटल पहुंच: भारतीय डाक सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है।
- सुविधा: डाकघरों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम हो जाती है।
- ट्रैकिंग: ग्राहकों को डाक और पार्सल से संबंधित लेनदेन को ट्रैक करने में मदद करता है।
- नागरिक-केंद्रित वितरण: सरकारी डाक सेवाओं तक तेज़ और अधिक सुविधाजनक पहुंच का समर्थन करता है।

इंडिया पोस्ट के बारे में:

- डाक विभाग संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय डाक ने ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- इसका नेटवर्क इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), बचत योजनाओं, बीमा और वित्तीय समावेशन पहलों सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं का भी समर्थन करता है।
- गठन: 1 अक्टूबर 1854
- सचिव: श्री सुब्रत दास
- डायरेक्टर जनरल : श्री जितेंद्र गुप्ता
- मंत्री: ज्योतिरादित्य सिंधिया

परीक्षा फोकस बिंदु:

- ऐप: छत का किराया
- संगठन: इंडिया पोस्ट / डाक विभाग
- मंत्रालय: संचार मंत्रालय
- क्षेत्र: डाक और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
- मुख्य उद्देश्य: डाक सेवाओं के लिए डोरस्टेप पहुंच
- नीति से जुड़ाव: डिजिटल इंडिया और नागरिक-केंद्रित शासन
- इंडिया पोस्ट की स्थापना: 1854
- इंडिया पोस्ट नेटवर्क: दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क में से एक
- मुख्यालय: नई दिल्ली

सीबीआईसी और फार्मेक्सिल ने फार्मास्युटिकल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए



- फार्मेक्सिल भारत के फार्मास्युटिकल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक निर्यात संवर्धन परिषद है। यह भारतीय दवा कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में सहायता करता है और व्यापार से संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड:

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) ने भारत के फार्मास्युटिकल निर्यात को मजबूत करने और फार्मास्युटिकल उत्पादों के डायवर्सन और दुरुपयोग को रोकने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य सीमा शुल्क अधिकारियों और फार्मास्युटिकल निर्यात क्षेत्र के बीच समन्वय में सुधार करना है।

मुख्य बिंदु

- समझौता ज्ञापन सीबीआईसी और फार्मेक्सिल के बीच मजबूत सूचना-साझाकरण तंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है।
- यह उन मामलों की पहचान करने और उनका समाधान करने में मदद करेगा जहां भारत से निर्यात किए गए फार्मास्युटिकल उत्पादों को अनपेक्षित बाजारों में स्थानांतरित किया जा सकता है या अनधिकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- इस पहल से व्यापार सुविधा को मजबूत करने, अनुपालन में सुधार और भारतीय फार्मास्युटिकल निर्यात की विश्वसनीयता बढ़ाने की उम्मीद है।
- बेहतर समन्वय से सीमा शुल्क अधिकारियों और उद्योग को फार्मास्युटिकल शिपमेंट से जुड़े जोखिमों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब देने में मदद मिलेगी।

फार्मेक्सिल के बारे में:

- गठन: 26 जनवरी 1944
- मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत
- निर्वाचित अधिकारी: निर्मला सीतारमण, भारत के वित्त मंत्री
- अध्यक्ष: विवेक चतुर्वेदी
- भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र – परीक्षा तथ्य
- वैश्विक स्तर पर सस्ती जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत को आमतौर पर "विश्व की फार्मसी" के रूप में वर्णित किया जाता है।
- भारत जेनेरिक दवाओं और टीकों के दुनिया के प्रमुख उत्पादकों में से एक है।
- फार्मास्युटिकल क्षेत्र भारत के व्यापारिक निर्यात का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी पहलों के माध्यम से फार्मास्युटिकल विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देती है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

व्यक्तियों	विवरण
समझौता ज्ञापन	सीबीआईसी-फार्मेक्सिल
वस्तुनिष्ठ	फार्मास्युटिकल निर्यात को मजबूत करना और उत्पाद के डायवर्सन को रोकना
सीबीआईसी	वित्त मंत्रालय
फार्मेक्सिल	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

मुख्य तंत्र	जानकारी साझा करना
क्षेत्र	फार्मास्यूटिकल्स और विदेश व्यापार

पॉलिसी लिंकेज	व्यापार सुविधा और एक्सपोर
---------------	---------------------------

सिटीग्रुप-एक्सिस बैंक ने एनआरआई डॉलर प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया



- सिटीग्रुप और एक्सिस बैंक ने एक्सिस बैंक के साथ विदेशी मुद्रा जमा में निवेश करने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए वित्तपोषण की सुविधा के लिए एक व्यवस्था में प्रवेश किया है। यह व्यवस्था भारत में डॉलर के प्रवाह को बढ़ाने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार का समर्थन करने में मदद कर सकती है।

मुख्य बिंदु

- इस व्यवस्था के तहत, एक्सिस बैंक अपने अपतटीय संचालन के माध्यम से सिटीग्रुप द्वारा प्रदान किए गए वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट (एसबीएलसी) जारी करेगा।
- यह संरचना एनआरआई को विदेशी मुद्रा जमा में निवेश की गई राशि के खिलाफ वित्तपोषण प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे विदेशी मुद्रा प्रवाह के लिए एक लीवरेज्ड मार्ग बनता है।
- यह पहल विदेशी मुद्रा जमा को आकर्षित करने और भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति को मजबूत करने के लिए आरबीआई के उपायों के बीच की गई है।
- एक्सिस बैंक एफसीएनआर (बी) जमा पर 6.40% तक की ब्याज दरें प्रदान करता है।
- RBI ने जून 2026 में बैंकों को NRI से FCNR(B) जमा जुटाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक रियायती FX स्वेप सुविधा शुरू की थी।
- मजबूत जुटाव के कारण, RBI ने बाद में स्वेप विंडो की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया।

महत्व

- विदेशी मुद्रा भंडार: उच्च विदेशी मुद्रा जमा भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता है।
- रुपये की स्थिरता: डॉलर का प्रवाह भारतीय रुपये पर दबाव को कम करने में मदद कर सकता है।
- एनआरआई भागीदारी: यह व्यवस्था एनआरआई को भारतीय बैंक जमा में निवेश करने के लिए एक अतिरिक्त वित्तपोषण तंत्र प्रदान करती है।

- वैश्विक बैंकिंग: यह सिटी जैसे विदेशी बैंक को भारत में खुदरा बैंकिंग नेटवर्क बनाए रखे बिना अपतटीय वित्तपोषण के माध्यम से भाग लेने में सक्षम बनाता है।

महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि:

- सिटीग्रुप ने 2022 में भारत के उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसाय से बाहर निकल गया, अपने उपभोक्ता व्यवसायों को एक्सिस बैंक को बेच दिया। वर्तमान व्यवस्था भारतीय खुदरा बैंकिंग में सिटी की वापसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है; सिटी काफी हद तक संस्थागत ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है।

अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य: एफसीएनआर (बी)

- FCNR(B) का मतलब विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता है।
- एनआरआई और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के लिए उपलब्ध।
- जमाराशियों को विदेशी मुद्रा में रखा जाता है, जिससे जमाकर्ताओं को रुपये की विनिमय दर के जोखिम से बचाया जाता है।
- एफसीएनआर (बी) खातों को सावधिक/सावधि जमाराशियों के रूप में रखा जाता है।
- अनुमेय मुद्राएं भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत निर्दिष्ट की जाती हैं।
- एफसीएनआर (बी) खाते विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) ढांचे के तहत शासित होते हैं।

परीक्षा फोकस बिंदु:

व्यक्तियों	विवरण
शामिल बैंक	सिटीग्रुप और एक्सिस बैंक
उद्देश्य	एनआरआई विदेशी मुद्रा जमा और डॉलर प्रवाह में वृद्धि
मुख्य साधन	स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट (SBLC)
जमा प्रकार	एफसीएनआर (बी)
नियामक	आरबीआई
लक्ष्य समूह	एनआरआई
नीति का उद्देश्य	विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना और रुपये की स्थिरता का समर्थन करना
स्वेप सुविधा की समय सीमा	31 अगस्त 2026

एके-203 'शेर': भारत ने पहली 100% स्वदेशी राइफल का परीक्षण किया



- भारत ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरवा संयंत्र में पहली 100% भारतीय AK-203 'शेर' असॉल्ट राइफल के सफल निर्माण और परीक्षण-फायरिंग के साथ रक्षा स्वदेशीकरण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रोटोटाइप में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक घटक और इनपुट सामग्री को भारतीय उद्योग से प्राप्त किया गया था।

आपूर्ति करनी है। डिलीवरी को दिसंबर 2030 के लिए लक्षित किया गया है, जो मूल अक्टूबर 2032 के शेड्यूल से आगे है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- आत्मनिर्भर भारत: 100 प्रतिशत स्वदेशी संस्करण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/स्थानीय असेंबली से पूर्ण घरेलू विनिर्माण की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
- रक्षा तैयारी: AK-203 का उद्देश्य भारतीय सेना की छोटे हथियारों की सूची का आधुनिकीकरण करना है।
- औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र: इस परियोजना में भारतीय रक्षा उद्योग और एमएसएमई शामिल हैं, जो घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करते हैं।
- रणनीतिक स्वायत्तता: स्वदेशी उत्पादन महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों के लिए आयातित घटकों पर निर्भरता को कम करता है।

मुख्य बिंदु

- राइफल का निर्माण भारत-रूसी राइफल प्राइवेट लिमिटेड (आईआरएपीएल) द्वारा किया गया है, जो 2019 में स्थापित भारत-रूस संयुक्त उद्यम है।
- प्रोटोटाइप ने उत्साहजनक प्रारंभिक परिणामों के साथ बर्स्ट फायरिंग सहित सफलतापूर्वक फायरिंग परीक्षण किए हैं।
- सितंबर 2026 में भारतीय सशस्त्र बलों के परीक्षणों के लिए अतिरिक्त पूरी तरह से स्वदेशी राइफलों का उत्पादन किया जाएगा।
- आईआरपीएल हर 100 सेकंड में एक राइफल की उत्पादन दर को लक्षित कर रहा है।
- मौजूदा 5,200 करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत, आईआरएपीएल को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 6,01,427 एके-203 राइफलों का निर्माण और

परीक्षा फोकस बिंदु:

व्यक्तियों	विवरण
AK-203 'शेर'	स्वदेशी असॉल्ट राइफल
में निर्मित	कोरवा, अमेठी, उत्तर प्रदेश
निर्माता	आईआरपीएल
भागीदार	भारत और रूस
स्वदेशीकरण	100%
इक्रारनामा करना	6,01,427 राइफलों के लिए ₹5,200 करोड़
बीमा पॉलिसी	मेक इन इंडिया / आत्मनिर्भर भारत
सेना परीक्षण	सितंबर 2026

लेट्स रिवाइज

- ❖ भारत-चीन सीमा प्रश्न पर 25 वीं विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? **अजीत डोभाल**।
- ❖ किस संगठन ने तीन स्वदेशी सूक्ष्म और लघु गैस टरबाइन इंजनों का अनावरण किया? **सीएसआईआर-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाएं (सीएसआईआर-एनएएल)**।
- ❖ एफआईपी अवार्ड्स 2026 में प्रकाशन विभाग को कितने पुरस्कार मिले? **सात**।
- ❖ तमिलनाडु योजना का नाम क्या है जो सालाना तीन एलपीजी सिलेंडरों के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करती है? **अन्नपूर्णा सुपर सिक्स योजना**।
- ❖ ई-श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? **26 अगस्त 2021**।
- ❖ किस नियामक निकाय ने 1,800 किलोमीटर नई एलपीजी पाइपलाइनों को मंजूरी दी? **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी)**।
- ❖ डाक सेवा ऐप किस सरकारी पहल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? **डिजिटल इंडिया**।
- ❖ किन दो संगठनों ने फार्मास्युटिकल निर्यात को मजबूत करने और उत्पाद डायवर्सिफिकेशन को रोकने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? **सीबीआईसी और फार्मेक्सिल**।
- ❖ एनआरआई विदेशी मुद्रा जमा का लाभ उठाने के लिए किन दो बैंकों ने भागीदारी की है? **सिटीग्रुप और एक्सिस बैंक**।
- ❖ भारत की पहली 100% स्वदेशी AK-203 'शेर' का परीक्षण कहाँ किया गया था? **कोरवा सुविधा, अमेठी, उत्तर प्रदेश**।



The **ACHIEVERS** IAS ACADEMY PATNA

Daily **NEWS CHRONICLE**

IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS IN UPSC EXAMINATIONS

Current Affairs hold a crucial place in the preparation for the UPSC Civil Services Examination. A comprehensive understanding of recent national and international developments helps aspirants strengthen their General Studies foundation and develop a well-rounded perspective on important issues. Topics such as government policies, schemes, economy, international relations, science and technology, environment, defence, social justice, governance, reports, indices, appointments, awards, and major global events are highly relevant for both the Prelims and Mains examinations. Regular study of current affairs not only enhances factual knowledge but also improves analytical ability, critical thinking, answer-writing skills, and decision-making aptitude. Since UPSC questions often connect contemporary developments with static subjects, consistent preparation of current affairs enables aspirants to understand issues in depth and present balanced, informed, and relevant answers. It also plays an important role in Essay writing, Ethics, and the Personality Test, giving candidates a strong edge throughout the examination process.

CONTACT US



+91 8434931877



achievers_ias_patna



PATLIPUTRA GOLAMBAR



ACHIEVERS IAS ACADEMY (UPSC/BPSC)



achieversiaspatna@gmail.com



Achievers IAS Academy



www.achieversiaspatna.co.in



Achievers IAS Academy, PATNA